

भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3088

बुधवार, 19 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

गगनयान-1 मिशन

3088. श्री इमरान मसूद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गगनयान-1 मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है तथा इसके विभिन्न श्रेणियों में कितना व्यय किया गया है;
- (ख) क्या मिशन के लिए प्रारंभिक बजट आवंटन के बाद से कोई परिवर्तन या संशोधन किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या निजी क्षेत्र भी गगनयान-1 मिशन के लिए सहयोग कर रहा है तथा यदि हां, तो गगनयान-1 मिशन के विकास में शामिल निजी उद्यमों के नाम क्या हैं तथा उनका विशेष योगदान क्या है; और
- (ङ) अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण करने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का निजी उद्यमों के सहयोग संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) गगनयान कार्यक्रम को वर्तमान में ~20,193 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी गई है। परिकल्पित व्यय को राजस्व (~341 करोड़) और पूंजी (~19852 करोड़) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो आवश्यक प्रौद्योगिकी विकास संबंधी गतिविधियों और मानव रहित/मानवयुक्त उड़ान मिशनों को आयोजित करने के लिए है। (कुल: 8 संख्या)।
- (ख) एवं (ग)

जी हां, गगनयान कार्यक्रम के दायरे और वित्तीय मंजूरी में संशोधन किया गया है। अमृत काल में अंतरिक्ष के विज्ञान में अन्य बातों के साथ-साथ, 2035 तक एक प्रचालनात्मक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और 2040 तक भारतीय कर्मिदल युक्त चंद्र मिशन की परिकल्पना की गई है। लंबी अवधि के भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशनों को सुसाध्य बनाने के लिए इन नई क्षमताओं के निर्माण की दिशा में, विभिन्न प्रौद्योगिकियों को विकसित और अधिप्रमाणित किया जाना है। संशोधित दायरे के अनुसार, इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन चरणबद्ध रूप में आठ मिशनों (2 कर्मिदल युक्त+ 6 कर्मिदल रहित) के माध्यम से करने की योजना बनाई गई है।

- (घ) इसरो सहयोगी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें इस मिशन में प्रदर्शित करने की योजना है। निजी उद्यम इस कार्यक्रम में, विशेष रूप से प्रमोचन यान प्रणालियों, उप-प्रणालियों और भू/उड़ान परीक्षण कार्यक्रम, कर्मीदल मॉड्यूल पुनःप्राप्ति मॉडल, वर्चुअल रियलिटी आधारित प्रशिक्षण अनुकारक, स्वदेशी पर्यावरण नियंत्रण और जीवन सहायता प्रणाली (ईसीएलएसएस) के विभिन्न उप-प्रणालियों के साथ-साथ भू-अनुकारों के लिए उड्डयानिकी पैकेज जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचनाओं (अनुकारी कर्मीदल मॉड्यूल/ कर्मीदल मॉड्यूल) के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। योगदान देने वाले इन निजी उद्यमों में से कुछ हैं-टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, टाटा एलेक्सी, लार्सन एंड टुब्रो, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज, मंजीरा मशीन बिल्डर्स, गोदरेज एयरोस्पेस, डेटा पैटर्न इंडिया, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स आदि।
- (ङ) जून, 2020 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की, ताकि निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ाने हेतु आद्योपांत सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। अंतरिक्ष सुधार संबंधी विज्ञान को लागू करने के लिए एक व्यापक, समग्र और गतिशील ढांचे के रूप में अप्रैल 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 जारी की गई थी। यह वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत के बड़े हिस्से को लक्षित करते हुए मजबूत, अभिनव और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष परितंत्र विकसित करने के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की मूल्य शृंखला में गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह एनजीई को सार्वजनिक निधि के माध्यम से बनाए गए बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में भी सक्षम बनाता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया गया, जिससे विभिन्न अंतरिक्ष क्षेत्रों में विदेशी निवेश की उच्च सीमा संभव हो पाई। गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीईएस) की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, विनियमित करने और प्राधिकृत करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक एकल-खिड़की एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया गया था। इसके अलावा, इन-स्पेस के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए विभिन्न इसरो केंद्रों की सुविधाओं के निजी क्षेत्र द्वारा उपयोग की भी अनुमति दी जाएगी। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल), अंतरिक्ष विभाग के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो इसरो द्वारा विकसित परिपक्व प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करेगा। इसरो गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रोटोकॉल, प्रलेखन, परीक्षण प्रक्रियाओं आदि पर अपने अनुभवों को साझा करके भारतीय अंतरिक्ष उद्योगों का पोषण भी करेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में चुनौतियां पेश करते हुए 'भारतीय उद्योग के माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/प्रणालियों के विकास में आत्मनिर्भरता' जैसे अवसरों की घोषणा और प्रयास भी किए जा रहे हैं।